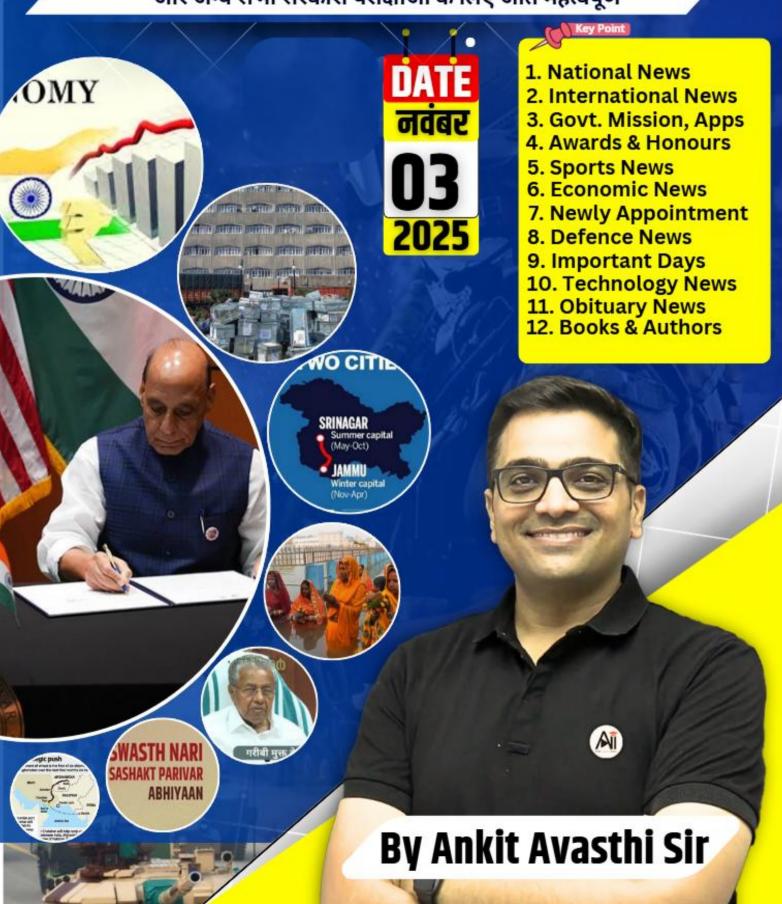
# **RNA: Real News Analysis**

# DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE, और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण







## भारत का ३० ट्रिलियन डॉलर का विजन / India's \$30 Trillion Vision

#### संदर्भ:

बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री **पीयूष गोयल** ने कहा कि आने वाले **२० से 25 वर्षों में भारत 30 टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनेगा। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक दृष्टि न केवल भारत की विकास यात्रा को परिभाषित करेगी, बल्कि भविष्य में **व्यापार** समझौतों पर भारत की वार्ता रणनीति और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में उसकी भूमिका को भी नया स्वरूप देगी।

#### भारत की अर्थव्यवस्था और GDP: प्रमुख तथ्य

#### GDP क्या है

- किसी देश की आर्थिक आकार (Size of the Economy) उसके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product – GDP) से मापा जाता है।
- GDP वह कुल बाजार मूल्य है, जो किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का होता है।

#### GDP कैसे मापा जाता है?

- घरेलू स्तर पर GDP रुपयों में मापा जाता है, और वैश्विक तुलना के लिए इसे अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाता है।
- उदाहरण: a₹330 ट्रिलियन ÷ ₹84 (विनिमय दर) = \$3.9 ट्रिलियन।
- यदि रुपये में GDP बढ भी जाए, लेकिन रुपया कमजोर हो जाए, तो डॉलर में GDP का मूल्य घट जाता है।

#### GDP के प्रकार:

- **नाममात्र GDP:** इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है यानी वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि दर्शाता है।
- वास्तविक GDP: इसमें मुद्रास्फीति को हटाया जाता है, जिससे वास्तविक उत्पादन वृद्धि दिखाई देती है।

#### भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि (Projected Growth):

- वर्ष २००० से अब तक भारत के नाममात्र GDP में 11.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है।
- इसी अवधि में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले औसतन २.७% वार्षिक दर से अवमुल्यित हुआ है।
- यदि आने वाले २५ वर्षों में भी यही रुझान बना रहता है
  - GDP की वृद्धि दर 11.9% रहे, और
  - रुपया समान गति से कमजोर होता रहे, तो **भारत का GDP वर्ष 2048 तक S30 टिलियन से अधिक** हो जाएगा।

#### लक्ष्य के सामने चुनौतियाँ:

- भूतकालीन आँकडों के आधार पर भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाना तर्कसंगत लगता है, लेकिन २०१४ के बाद भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी हुई है।
- पिछले 11 वर्षों में भारत का नाममात्र GDP 10.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढा है, जो पिछले 25 वर्षों के 11.9% औसत से कम है।
- इसी अवधि में रुपये का अवमूल्यन 3.08% वार्षिक दर से हुआ है, जो पहले के 2.7% की तुलना में अधिक है।
- इसका अर्थ है कि अब आर्थिक वृद्धि धीमी है, जबकि मुद्रा और तेजी से कमजोर हो रही है।
- यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो भारत का GDP \$30 ट्रिलियन तक केवल वर्ष २०५५ के आसपास पहुँचेगा, न कि २०४८ तक।
- इस तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा निर्धारित लक्ष्य लगभग एक दशक पीछे खिसक सकता है।

#### सरकारी पहलें:

- मेक इन इंडिया: घरेलू विनिर्माण को बढावा देकर GDP में उद्योग की हिस्सेदारी २५% तक लाने का लक्ष्य।
- PLI योजना: 14 प्रमुख क्षेत्रों में बडे पैमाने पर निर्माण, निर्यात और रोजगार बढावा।
- राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम: आधुनिक औद्योगिक ढांचा और कनेक्टिविटी विकास।
- पीएम गतिशक्ति (2021): सडकों, रेल, बंदरगाहों व लॉजिस्टिक्स को जोडने की एकीकृत योजना।
- भारतमाला व सागरमालाः सडक और बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार से लॉजिस्टिक लागत में कमी।
- स्किल इंडिया मिशन: युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुशल कार्यबल तैयार करना।
- स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया: नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन।
- **FTA समझौते:** UK, EU, UAE आदि देशों के साथ निर्यात बाजारों का विस्तार।
- एक्ट ईस्ट व इंडो-पैसिफिक नीतिः एशिया-प्रशांत क्षेत्र से आर्थिक व रणनीतिक संबंध मजबूत करना।











# RNA DAILY CURRENT AFFAIRS



## भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग / India-US Defence Cooperation

#### संदर्भ:

भारत और अमेरिका ने 31 अक्टूबर 2025 को एक नए **10 वर्षीय रक्षा रुपरेखा समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को गहरा करना तथा "मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत" सुनिश्चित करना है। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हगसेथ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो 2015 के पूर्ववर्ती ढांचे को प्रतिस्थापित करते हुए उसे और सशक्त बनाता है।

#### भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का नया ढांचा:

- **एकीकृत नीति दिशा:** यह ढांचा सैन्य, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट और संगठित नीति रोडमैप प्रदान करता है।
- तकनीकी और औद्योगिक सहयोग: दोनों देशों ने उन्नत रक्षा प्रणालियों के सह-उत्पादन और सह-विकास को बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें भारत में "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल पर विशेष जोर दिया गया है।
- सूचना और खुफिया साझेदारी: साइबर और समुद्री सुरक्षा जैसे उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए खुफिया आदान-प्रदान और समन्वय तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** युध अभ्यास, मालाबार और टाइगर ट्रायम्फ जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के दायरे को और विस्तारित किया जाएगा।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता:** दोनों देश मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या प्रभुत्ववादी गतिविधियों को रोका जा सके।

#### भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग:

- प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP): अमेरिका ने 2016 में भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" का दर्जा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक नए स्तर पर पहुंचा।
- **महत्वपूर्ण समझौते (२०१६–२०२०):** इस अवधि में चार बड़े समझौते हुए
  - LEMOA (2016): लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिससे दोनों
     देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के बेस उपयोग की अनुमित मिली।
  - COMCASA (2018): संचार सुरक्षा और संगतता समझौता, जिससे सुरक्षित संचार और डेटा साझा करना संभव हुआ।
  - BECA (2020): बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो भू-स्थानिक खुफिया साझा करने से जुड़ा है।
- **नए समझौते (२०२४):** दोनों देशों ने **सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट (SOSA)** और **लायज़न ऑफिसर्स की नियुक्ति पर समझौता** सहित कई नए रक्षा समझौते किए, जिससे आपसी समन्वय और सुरक्षा सहयोग और मजबूत हुआ।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास (२०२५): भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने 'युध अभ्यास' नामक दो-सप्ताह का संयुक्त अभ्यास अलास्का के **फोर्ट वेनराइट** में आयोजित किया।

#### भारत का दृष्टिकोण से महत्त्व:

- स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा: यह समझौता "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को मजबूती देता है।
- महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच: यह भारत को अमेरिकी
  रक्षा तकनीक और महत्वपूर्ण "नॉ-हाउ" तक संस्थागत
  पहुंच प्रदान करता है जैसे जेट इंजन और हाइपरसोनिक
  सिस्टम निर्माण जिससे रूस पर निर्भरता कम होगी।
- सैन्य आधुनिकीकरण में वृद्धिः MQ-98 ड्रोन और F-414
   जेट इंजन जैसे आधुनिक अमेरिकी हथियार प्रणालियों
   तक पहुंच भारत की सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाती है।
- रणनीतिक स्वायत्तता में सुधार: विविध स्रोतों से रक्षा
   उपकरण प्राप्त कर और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर भारत
   अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता मजबूत कर रहा है।
- वैश्विक स्थिति में उन्नित: यह समझौता भारत को अमेरिका का "मेजर डिफेंस पार्टनर" बनाता है और क्षेत्रीय स्थिरता के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ाता है।

#### अमेरिका का दृष्टिकोण से महत्तः

- क्षेत्रीय प्रभाव में विस्तार: यह समझौता इंडो-पैसिफिक में चीन से प्रतिस्पर्धा के बीच भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार के साथ सहयोग बढ़ाकर अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करता है।
- सैन्य सहयोग और तालमेल: इस ढांचे से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभियानों और अभ्यासों में बेहतर तालमेल और सामंजस्य स्थापित होगा।
- रणनीतिक संरेखण गहरानाः अमेरिका भारत को एक लोकतांत्रिक मूल्य आधारित साझेदार मानता है, जो "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक"दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है।
- औद्योगिक साझेदारी को बल: समझौता अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत के बढ़ते निर्माण क्षेत्र से जोड़ता है, उत्पादन और आपूर्ति शृंखला साझेदारी मजबूत होती है।
- पूर्व समझौतों पर आधारित सहयोग: यह ढांचा LEMOA,
   COMCASA और BECA जैसे पुराने समझौतों पर आधारित
   है, जो पहले से ही लॉजिस्टिक्स, संचार और इंटेलिजेंस साझेदारी को गहराई दे चुके हैं।















# दरबार मूव / Darbar Move

#### संदर्भ:

चार वर्ष के अंतराल के बाद, **जम्मू-कश्मीर सरकार** ने मुख्यमंत्री **उमर अब्दुल्ला** के नेतृत्व में दिवार्षिक दरबार मृव (Darbar Move) परंपरा को फिर से शुरू किया है। वर्ष 2025 में अधिकारी और सरकारी कार्यालय गर्मियों की राजधानी श्रीनगर से सर्दियों की राजधानी जम्मू की ओर स्थानांतरित होना प्रारंभ हुए हैं। यह ऐतिहासिक प्रथा आखिरी बार 2021 में लागू की गई थी।

#### दरबार मूव (Darbar Move): जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक प्रशासनिक परंपरा-

परिभाषा: दरबार मूव जम्मु-कश्मीर की एक द्विवार्षिक परंपरा थी, जिसके तहत राज्य सरकार और प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों को साल में दो बार राजधानी बदलनी होती थी — गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू।

#### डतिहास:

- इस परंपरा की शुरुआत 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने की थी।
- उद्देश्य था श्रीनगर की कठोर सर्दियों से बचना और राज्य के दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करना।

#### समाप्ति (२०२१):

- **जून २०२१** में जम्मू-कश्मीर के **लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन** ने इस परंपरा को समाप्त
- इस निर्णय से **हर साल लगभग ₹२०० करोड़ की बचत** होने का अनुमान लगाया
- अब "**ई-ऑफिस प्रणाली**" के तहत दोनों शहरों में सालभर काम डिजिटल रूप में होता है।

#### विवाद और आलोचना:

- आलोचकों ने कहा कि इस कदम से जम्मू और कश्मीर के बीच संबंध कमजोर होंगे।
- साथ ही, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर ट्रांसपोर्ट, होटल और छोटे कारोबारों – को नुकसान हुआ।

#### दरबार मूव की बहाली का प्रभाव:

#### आर्थिक प्रभाव:

- जम्मू की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: दरबार मूव की वापसी से जम्मू की सर्दियों की **अर्थव्यवस्था को बडा सहारा** मिलेगा। २०२१ में परंपरा रुकने के बाद होटलों, परिवहन सेवाओं और बाजारों में गतिविधि कम हो गई थी।
- लागत को लेकर चिंता: विरोधियों का कहना है कि इस कदम से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पडेगा, क्योंकि हर साल दफ्तरों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर काफी खर्च होता है।

कर्मचारियों की मिली-जुली राय: कुछ कर्मचारी इसे क्षेत्रीय जुडाव बनाए रखने का साधन मानते हैं, जबकि अन्य इसे पारिवारिक जीवन में व्यवधान पैदा करने वाला बताते हैं।



#### राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

- प्रतीकात्मक महत्तः दरबार मूव की बहाली को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच प्रशासनिक एकता का प्रतीक थी।
- राजनीतिक संदेश: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत दरबार मूव को बहाल किया है, जिससे विशेषकर जम्मू क्षेत्र के मतदाताओं से राजनीतिक जुड़ाव मजबूत हुआ है।
- कार्यक्षमता पर सवाल: आलोचकों का मानना है कि डिजिटल युग में जब ई-ऑफिस प्रणाली उपलब्ध है, तो दफ्तरों का भौतिक रूप से स्थानांतरण अप्रभावी और पुरानी प्रथा है।

#### मुख्य विशेषताएँ (दरबार मूव की बहाली):

- समय-सारणी: अब सरकारी दफ्तर और कर्मचारी हर साल *मई से अक्टूबर* तक श्रीनगर में और *नवंबर से अप्रैल* तक जम्मु में कार्य करेंगे।
- लॉजिस्टिक्स: इस बडे पैमाने की प्रक्रिया में हजारों कर्मचारियों, सरकारी फाइलों, दस्तावेज़ों और कंप्यूटरों को *जम्मू-श्रीनगर हाईवे* के ज़रिए ट्रकों व बसों से ले जाया जाता है। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियों की विशेष जरूरत होती है।









# 01 नवंबर २०२५



## भारत ने छठ पूजा को यूनेस्को से मान्यता दिलाने की वकालत / India Advocates for UNESCO Recognition of Chhath Puja

#### संदर्भ:

भारत सरकार ने छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक घरोहर (Intangible Cultural Heritage) सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नामांकन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में की थी। यह पहल इस पर्व के गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है, जो भारत की लोक आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

#### छठ पूजा: यूनेस्को मान्यता की दिशा में भारत का प्रयास:

#### 1. पर्व का परिचय:

- छठ एक प्राचीन चार दिवसीय हिन्दू पर्व है जो सूर्य देव और उनकी शक्ति छठी मझ्या
   (उर्वरता व कल्याण की देवी) को समर्पित है।
- मुख्य रूप से *बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश* में मनाया जाता है, साथ ही विश्वभर में भारतीय प्रवासी समुदाय भी इसे मनाते हैं।
- इस पर्व में उपवास, सूर्य को "अर्घ्य" अर्पित करना, और प्राकृतिक जलाशयों में पूजा-अर्चना की जाती है।
- यह पर्व *हिंदू माह कार्तिक* (अक्टूबर-नवंबर) में मनाया जाता है।

#### 2. यूनेस्को मान्यता की मांग के प्रमुख कारण:

- पर्यावरणीय महत्तः यह प्रकृति के साथ संतुलित संबंध का प्रतीक है श्रद्धालु नदी घाटों की सफाई करते हैं और बाँस की टोकरी व मिट्टी के दीपक जैसे पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग करते हैं।
- **सामाजिक एकता:** छठ पूजा जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सामाजिक समानता और सामूहिकता का संदेश देती है।
- **सांस्कृतिक संवर्धन:** यूनेस्को की मान्यता भारत की प्राचीन और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगी।
- प्रवासी भारतीय जुड़ाव: यह प्रयास विदेशों में बसे भारतीय समुदायों के सांस्कृतिक गर्व और पहचान को और सशक्त करेगा।

#### 3. 2026–27 के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन:

- *सितंबर २०२५* में संस्कृति मंत्रालय ने *सूरीनाम, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात* के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया।
- इन देशों का चयन वहाँ के प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा छठ पूजा के व्यापक आयोजन के कारण किया गया।
- यह पहल 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल दुर्गा पूजा की तरह एक बहुराष्ट्रीय नामांकन मॉडल पर आधारित है।
- *संगीत नाटक अकादमी* संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में 2026-27 चक्र के लिए छठ पूजा का दस्तावेज़ तैयार कर रही है।

#### 4. संभावित मान्यता का प्रभाव:

- वैश्विक पहचान: छठ पूजा को विश्व मंच पर मान्यता मिलेगी और इसकी परंपराएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी जाएँगी।
- सांस्कृतिक पर्यटन में वृद्धिः मान्यता से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।
- संरक्षण और दस्तावेज़ीकरणः पर्व की परंपराओं को व्यवस्थित रूप से संरक्षित और भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया जा सकेगा।
- मूल्यों का प्रसारः पर्यावरण संरक्षण, समानता और अनुशासन के मूल्य वैश्विक स्तर पर और मजबूत होंगे।

#### यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage — ICH) रुपरेखा

#### १. स्थापना और उद्देश्य:

- यूनेस्को ने *2003 के "Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage"* के तहत *2008 में* अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (ICH List) की स्थापना की।
- इसका उद्देश्य जीवंत परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामुदायिक रीतियों की पहचान, संरक्षण और संवर्धन करना है।

#### 2. मान्यता का दायरा:

- सूची में *लोक कला, पारंपरिक संगीत, नृत्य, अनुष्ठान, उत्सव और सामाजिक परंपराएँ* शामिल की जाती हैं।
- यह उन सांस्कृतिक रूपों को सम्मान देती है जो किसी समुदाय की पहचान, निरंतरता और सामूहिक स्मृति को दर्शाते हैं।

#### 3. भारत की स्थिति:

- भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व इस सूची में पहले से शामिल हैं।
- प्रमुख उदाहरण: *योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, और नवरोज्*।
- भारत का लक्ष्य अपनी विविध और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को इस वैश्विक मंच पर और अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना है।











# 01 नवंबर 2025



#### केरल ने अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन किया / Kerala eradicated extreme poverty

#### संदर्भ:

केरल के मुख्यमंत्री **पिनराई विजयन** ने राज्य को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया, जिससे केरल यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह घोषणा केरल पिरवी दिवस (राज्य स्थापना दिवस) के अवसर पर की गई, जो राज्य के **चार वर्षीय अत्यधिक गरीबी उन्मुलन** कार्यक्रम (Extreme Poverty Eradication Programme - EPEP) की सफल पूर्णता के बाद आई है।

#### अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम: EPEP-

- **1. कार्यान्वयन:** २०२१ में शुरू किया गया कार्यक्रम केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्टेशन और स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित किया गया।
- यह मिशन केरल की *विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली* और *कुडुंबश्री* नामक सामुदायिक नेटवर्क की ताकत पर आधारित था।

#### २. पहचान प्रक्रियाः

- प्रारंभिक सर्वेक्षण में *1.18 लाख* कमजोर परिवारों की पहचान की गई।
- सत्यापन के बाद *६४,००६ परिवारों* (कुल *१,०३,०९९ सदस्य*) को अत्यंत गरीबी में रहने वाला घोषित किया गया।
- पहचान *चार संकेतकों* पर आधारित थी **खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य,** आवास. और आय।

#### 3. सुक्ष्म योजनाएँ (Micro-plans):

- प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाई गई।
- त्वरित राहत जैसे फूड किट, चिकित्सीय सहायता, और आवश्यक दस्तावेज़ (राशन कार्ड, आधार कार्ड) सुनिश्चित करना शामिल था।

#### 4. प्रमुख हस्तक्षेप:

- आवास: ५,४२२ नए मकान बनाए गए और ५,५२२ की मरम्मत की गई। 439 परिवारों को भूमि भी दी गई।
- **जीविका:** ४,३९४ परिवारों को *स्वरोज़गार सहायता* दी गई, और कई मरिवारों को रोजगार से जोडा गया।
- रवाद्य सुरक्षा: जिन परिवारों के पास नियमित भोजन की कमी थी, उन्हें *फूड किट और पका हुआ भोजन* उपलब्ध कराया गया।

#### ५. बजट प्रावधान:

- *₹५० करोड* (२०२३-२४)
- ₹*50 करोड* (2024-25)
- ₹*60 करोड* (2025-26)

### स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान / Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan

#### संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी अभियान "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" के तहत तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत में **महिलाओं के** स्वास्थ्य सशक्तिकरण और परिवार कल्याण को बहावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान (Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan):

#### 1. अभियान का परिचय:

- प्रधानमंत्री द्वारा *17 सितंबर से 2 अन्तूबर 2025* तक राष्ट्रीय अभियान "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" की शुरुआत की गई।
- यह अभियान *पोषण माह (Poshan Maah)* के साथ मिलकर मनाया गया।
- इसका उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषणको सुदृढ़ करना है।
- 2. मुख्य उपलब्धियाँ (Guinness World Records): भारत ने इस अभियान के तहत कई विश्व रिकॉर्ड हासिल किए –
  - एक माह में सबसे अधिक लोगों का हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण।
  - एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों का ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पंजीकरण।
  - राज्य स्तर पर एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों का ऑनलाइन वाडटल साइन स्क्रीनिंग के लिए पंजीकरण।

#### 3. अभियान का महत्त:

- यह उपलब्धि *सरकारी तंत्र, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार,* और *जनसहभागिता* के सफल संयोजन का प्रमाण है।
- इस पहल से *महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी. जागरुकता* और *निवारक जांच* को नई गति मिली है।
- यह कदम "स्वस्थ नारी, सशक्त भारत" के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।















1500x4 26000/- 7 1 1

- 🥯 रोज़ाना लाइव क्लासेस
- सांप्ताहिक ट्रेस्ट्र
- 🛮 क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में) 🗟
- लाइव डाउट सेशन
- रोजाना प्रैक्टिस प्रश्न





## FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET LEARN HOW TO TRADE

# FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

E4000/-

**OFFER PRICE** 

₹2800/-



एक निवेश समझदारी से..









# FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

Invest in Knowledge Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-



एक निवेश समझदारी से..

# PURTFULIU BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

- (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
- > Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

**SPECIAL BONUS** 

TYEAR







